



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 13—जनवरी 19, 2007 (पौष 23, 1928)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 13—JANUARY 19, 2007 (PAUSA 23, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधित्त नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	13	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	21	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, निर्यंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	29
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	63	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	25
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	13
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	11
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	Page No. 13	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	Page No. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	21	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	29
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	63	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	25
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	13
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	11
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

सं. I-19017/2/2005-एन. आई.-II--भारत सरकार द्वारा, इस मंत्रालय की दिनांक 23 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना सं. I-11034/13/88-एन.आई.डी.-I और दिनांक 22 जुलाई, 1997 की अधिसूचना सं. I-11016/7/97-एन.आई.डी.-I (ए) में आंशिक संशोधन करते हुए, कबीर पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार की राशि को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:--

	से	तक
श्रेणी-I	1,00,000 रुपये	2,00,000 रुपये
श्रेणी-II	50,000 रुपये	1,00,000 रुपये
श्रेणी-III	25,000 रुपये	50,000 रुपये

ओ. पी. महे
निदेशक

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 दिसंबर 2006

सं. 11011/5/2003-रा. भा. (अनु.)--

संकल्प

संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अधीन 1978 में गठित की गई थी। समिति द्वारा सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, सरकारी कामकाज में प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी, कंप्यूटरीकरण एक चुनौती से संबंधित प्रतिवेदन का सातवां खंड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार इसे लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गई थी। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 13 जुलाई, 2005 के संकल्प सं. 11011/5/2003-रा.भा.(अनु.) के द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।

2. उक्त संकल्प के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन की विचाराधीन सिफारिश सं. 16.7(छ), 16.10(2)(क) से 16.10(2)(च), 16.12(क) एवं 16.12(ख) पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निर्देश हुआ है :

क्र.सं.	समिति की सिफारिश	निर्णय
16.7(छ)	अधिकारियों के लिए उनके द्वारा हिंदी में दिए जाने वाले व अन्य कार्यों के लिए राजभाषा विभाग वार्षिक कार्यक्रम में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करे तथा उनका अभिलेख (लेखा-जोखा) रखना अनिवार्य किया जाए तथा मुख्यालय/मंत्रालय सार पर इसकी समीक्षा सुनिश्चित की जाए।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में 'क', 'ख', 'ग' क्षेत्र के कार्यालयों के लिए तदनुसार 20% का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।
16.10(2)	भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन एक अतिरिक्त प्रकोष्ठ का गठन करके उसे निम्नलिखित दायित्व सौंपे :- (क) यह प्रकोष्ठ सभी मंत्रालयों/विभागों के सरकारी प्रकाशनों के मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा तथा इस प्रकार प्रकाशित साहित्य की सर्वसुलभता सुनिश्चित कराएगा। (ख) विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों में हिंदी प्रकाशनों की कमी को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करेगा एवं इस क्षेत्र में मौलिक लेखन एवं अन्य भाषाओं में उपलब्ध आवश्यक सामग्री का हिंदी में स्तरीय अनुवाद करने का कार्य सुनिश्चित करेगा। (ग) यह प्रकोष्ठ समस्त सरकारी प्रकाशनों को वर्गीकृत करते हुए एक सूची का संकलन करेगा तथा नियमित रूप से इसका प्रकाशन करेगा। इसके अतिरिक्त नवीन हिंदी प्रकाशनों की उपलब्धता तथा इसके स्रोतों की जानकारी देते हुए इसमें संशोधनों आदि की ताजा जानकारी उपलब्ध कराते हुए एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित करेगा। (घ) प्रकोष्ठ अपने इस प्रयोजन के लिए एक वेबसाइट निर्मित कराएगा तथा इसपर सरकारी प्रकाशनों की उपलब्धता के साथ-साथ हिंदी के प्रसार एवं प्रचार से संबंधित बाजार में विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी आदि प्रदान करेगा।	यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि इस बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के सहयोग से समुचित कार्यवाई करें। यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

	(च) यह प्रकोष्ठ मंत्रालयों/विभागों सरकारी उपक्रमों में हिंदी प्रकाशनों को उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव मदद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।
16.12(क)	विनिवेश के संदर्भ में समिति यह सिफारिश करती है कि जिस भी उपक्रम में सरकारी भागीदारी हो, चाहे कम हो या ज्यादा राजभाषा नीति यथावत लागू रहेगी।	यह सिफारिश स्वीकार्य नहीं पाई गई।
16.12(ख)	बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ स्वदेशी कंपनियों, जो अपने उत्पाद की बिक्री अथवा उसके प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, उनके लिए यह बाध्य किया जाए कि वे सरकार के साथ पत्राचार हिंदी में ही करें साथ ही सरकार भी उनके साथ पत्राचार हिंदी में ही करें।	यह सिफारिश स्वीकार्य नहीं पाई गई।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए।

पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी
संयुक्त सचिव

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली.110001, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

सं. एफ. 9-25/2000/यू-3--

जबकि पांच संघटक संस्थाओं वाले अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बदूर को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956" की धारा 3 के तहत इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा "समविश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किया गया था।

और जबकि इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा 'अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, अमृतापुरी, केरल' नामक एक और संस्था को उपर्युक्त समविश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया था।

और जबकि विद्यापीठम के अनुरोध और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 11 सितम्बर, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के द्वारा उपर्युक्त संघटक संस्था का नाम बदलकर 'अमृता स्कूल ऑफ एप्लाइड साइंसेज' करने की अनुमति प्रदान की थी।

और जबकि विद्यापीठम ने उपर्युक्त संघटक संस्था की नामावली बदलने के लिए फिर से आवेदन किया है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार 'अमृता स्कूल ऑफ एप्लाइड साइंसेज, अमृतापुरी, केरल' के नाम को तत्काल प्रभाव से बदलकर 'अमृता स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड साइंसेज, अमृतापुरी, केरल' करने की अनुमति प्रदान करती है।

2. अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयम्बदूर को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित अन्य सभी निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

सं० एफ. 9-25/2000/यू-3

जबकि “अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईंसेज, कोच्चि” सहित पांच संघटक संस्थाओं वाले अमृता विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बदूर को “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956” की धारा 3 के तहत उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिकसूचना के द्वारा “समविश्वविद्यालय” के रूप में घोषित किया गया था।

विद्यापीठम् के अनुरोध और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विद्यापीठम् की उपर्युक्त संघटक संस्था अर्थात् “अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साईंसेज, कोच्चि” के नाम को तत्काल प्रभाव से बदलकर ‘अमृता स्कूल ऑफ नर्सिंग, कोच्चि’ करने की अनुमति प्रदान करती है।

2. अमृता विश्व विद्यापीठम्, कोयम्बदूर को समविश्वविद्यालय का दर्जा देने से संबंधित अन्य सभी निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th December 2006

No. I-19017/2/2005-NI-II—

It has been decided by the Government of India, in partial modification of this Ministry's Notifications No. I-11034/13/88-NID.I dated 23rd April, 1990 and No.I-11016/7/97-NID.I (A) dated 22nd July, 1997, to further increase the amount of cash award for Kabir Puraskar with immediate effect as under :-

	<u>From</u>	<u>To</u>
Grade-I	Rs.1,00,000	Rs.2,00,000
Grade-II	Rs. 50,000	Rs.1,00,000
Grade-III	Rs.25,000	Rs.50,000

O. P. MAHEY
Director

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110003, the 29th December 2006

RESOLUTION

No. 11011/5//2003-OL (Research)—

The Committee of Parliament on Official Language was constituted in 1976 under section 4(1) of the Official Languages Act, 1963. The Committee submitted seventh part of its Report, relating to propagation of Hindi for official purposes, the position of Hindi in the field of Law, original use of Hindi in Government work, availability of publications relating to Administration and Finance in Hindi, position emerging after discussions with the representatives of States and Union Territories, the status of Hindi in the perspective of Globalization and the challenge of computerization to Hindi, to the President. In accordance with section 4(3) of the Official Languages Act, 1963, the Report was laid on the Table of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Copies of the Report were sent to all Ministries/ Departments of the Government of India and to all States/ Union Territory Governments. After considering the views expressed by various Union Ministries/ Departments and the States/ Union Territories Governments, it has been decided to accept most of the recommendations of the Committee in toto and some of them with modifications vide Deptt. Of Official Language, Ministry of Home Affairs Resolution No.11011/5/2003OL (Research) dated 13.07.2005.

In continuation of above Resolution the undersigned is directed to convey the Orders of the President made under section 4(4) of the Official Languages Act, 1963 on the under consideration recommendations No. 16.7(f), 16.10(2) (a) to(e), 16.12(a) and 16.12(b) made in the Report of the Committee as follows:

S. No	Recommendations of the Committee	Decision
16.7 (f)	Specific targets in respect of dictation in Hindi or for other work to be done in Hindi by the officers may be included in the Annual Programme of the Department of Official Language and it should be made mandatory for them to keep a record of this work and it should be ensured that the same is reviewed at Headquarter/ Ministry level.	This recommendation has been accepted and Department of Official Language has prescribed specific targets of 20% in the Annual Programme for the offices of Region A, B & C accordingly.
16.10 (2)	An additional Cell may be set up under the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language by the Government of India and be assigned the following responsibilities:- [a] This cell will ensure proper coordination among the original writing, translation and the publication work of Government publication of all Ministries / Departments and will also ensure easy availability of this published literature.	This recommendation has not been accepted.

	<p>[b] To tackle the scarcity of Hindi publications in the Ministries/ Departments/ Institutes relating to Research, Science and Technology field, the cell may draw a panel consisting of experts/ educationists of these areas and will ensure original writing as well as standardized translation in Hindi of the required material available in other languages.</p> <p>[c] This cell will compile a list classifying all the Government publications and will bring out the same regularly. In addition to this, it will also bring out a monthly bulletin providing fresh information regarding the availability of new Hindi publications and the sources from where these are available.</p> <p>[d] For this purpose the cell will create its own website and will update it with information relating to various useful software available in the market for expansion and propagation of Hindi along-with the availability of various Government Hindi publications.</p> <p>[e] In order to ensure the availability of Hindi publications in the Ministries/ Departments/ Undertakings, this cell will provide all sorts of help and guidance.</p>	<p>This recommendation has been accepted with the modification that Ministry of Science & Technology and Ministry of Human Resource Development may take appropriate action with the cooperation of Central Translation Bureau, Department of Official Language in this regard.</p> <p>This recommendation has not been accepted.</p> <p>This recommendation has been accepted.</p> <p>This recommendation has been accepted.</p>
16.12(a)	In the context of disinvestment, the Committee recommends that the status-quo with regard to the Official Language policy should be maintained in these enterprises irrespective of the government's large or small shareholding in them.	This recommendation has not been found acceptable.
16.12(b)	Correspondence in Hindi with the Govt. should be made mandatory for those MNC's as well as Domestic Companies who use Hindi to publicise and promote the sale of their products. At the same time the Government should also respond in Hindi.	This recommendation has not been found acceptable.

Order

Ordered that a copy of this resolution be sent to all the Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice-President Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Prime Minister's Office, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat, the Registrar General of the Supreme Court of India, the University Grants Commission, the Law Commission of India, the Bar Council of India etc.

This Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. VALSALA G. KUTTY
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-1, the 28th December 2006

No. F.9-25/2000-U.3

Whereas Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu comprising five of its constituent institutions was declared as a 'Deemed-to-be-University' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 13th January, 2003.

And whereas, one more institution viz., *Amrita Institute of Computer Technology, Amritapuri, Kerala* was also included under the ambit of the aforesaid Deemed-to-be-University vide this Ministry's notification of even number dated the 8th August, 2003.

And whereas, the Central Government, on the request of the Vidyapeetham and on the advice of the UGC in this respect, allowed the change of name of this constituent unit as '*Amrita School of Applied Sciences*' vide the notification of even number dated the 11th September, 2006.

And whereas the Vidyapeetham has again applied for a further change in the nomenclature of the aforesaid constituent institution.

The Central Government, on the advice of the UGC in the matter, do hereby allow the change of name of '*Amrita School of Applied Sciences, Amritapuri, Kerala*' as '*Amrita School of Arts and Sciences, Amritapuri, Kerala*' with immediate effect.

2. All the other terms and conditions of conferment of the status of 'Deemed-to-be-University' on to the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore shall remain unchanged.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

No. F.9-25/2000-U.3

Whereas Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu comprising five of its constituent institutions including "*Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi*" was declared as a 'Deemed-to-be-University' under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 13th January, 2003 for the purpose of the aforesaid Act.

The Central Government, on the request of the Vidyapeetham and on the advice of the University Grants Commission (UGC) in this respect, hereby allow the change of name of the aforesaid constituent institution of the Vidyapeetham, viz., '*Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi*' as '*Amrita School of Nursing, Kochi*' with immediate effect.

2. All the other terms and conditions of conferment of the status of 'Deemed-to-be-University' on to the Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore shall remain unchanged.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.